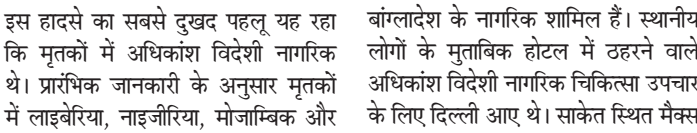




नवसर्जन संस्कृति

किंमत : 00.50 पैसा



है। दिल्ली। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर होती है, यदि वहाँ लोग अपने अधिकारों का दुरुपयोग सामान्य नागरिकों को भय और दबाव का शिकार बनाने लगें, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव कमजोर होने लगती है। इसी गंभीर चिंता को रखाँकित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने जबरन वसूली के आरोपों का सामना कर रहे तीन पुलिस अधिकारियों को मिली अग्रिम जमानत रद्द कर दी और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को कड़ा संदेश दिया। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब कानून के रक्षक ही कानून तोड़ने लगते हैं, तब आम नागरिकों का व्यवस्था पर से विश्वास उठमाने लगता है और वे भय तथा असुरक्षा की भावना से घिर जाते हैं। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें तीनों पुलिस अधिकारियों को अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश पर्याप्त रूप से स्पष्ट और तर्कसंगत नहीं था। अदालत ने अपने फैसले में यह भी रेखांकित किया कि वदीथारी अधिकारियों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग सामान्य अपराधों से अधिक गंभीर माना जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में पीड़ित के पास तत्काल प्रतिरोध करने की क्षमता बहुत सीमित होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जब कोई आम नागरिक पुलिस या अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के संपर्क में आता है, तो वह यह उम्मीद करता है कि उसके साथ न्यायपूर्ण और कानूनी व्यवहार होगा। लेकिन यदि वही अधिकारी अपनी पद और अधिकार का इस्तेमाल भय पैदा करने, धमकाने या अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए करें, तो नागरिकों के मन में कानून के प्रति सम्मान की जगह आशंका पैदा हो जाती है। अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसी परिस्थितियों में विरोध करना अक्सर तत्काल प्रतिक्रिया को आमंत्रित करने जैसा होता है, इसलिए अधिकारियों को मजबूती में चुनौती सब कुछ सहकर कर लेते हैं। मामला एक यात्री और उसके परिवार से जुड़ा है। शिकायतकर्ता अपनी बेटी के साथ मुंबई के रेलवे स्टेशन पर घुसने के लिए उनका एक थे। उन्हें स्टेशन छोड़ने के लिए उनका एक कि रेलवे स्टेशन पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तैनों को रोक लिया और रूखाछ के नाम पर हिरासत में ले लिया। इसके बाद उनके सामान की तलाशी भी हुई, जिसमें 14 ग्राम की एक सोने की छड़ और 31,900 रुपये नकद मिले। शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने सोने की छड़ और नकदी के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण भी दिया था। इसके बावजूद पुलिसकर्मों उन्हें स्टेशन परिसर के पास स्थित एक कमरे में ले गए। वहाँ कथित तौर पर उन्हें धमकाया गया, आमजनजनक भाषा का प्रयोग किया गया और नागरिक दबाव बनाया गया। आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने सोने की छड़ के बदले नकद राशि देने के लिए उन्हें मजबूर किया और अपनी शक्ति का अतृुत इस्तेमाल किया। घटना के बाद शिकायतकर्ता ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जज शुरु शुरू हुई और आरोपित पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की मांग की। हालांकि सत्र अदालत ने मामले की परिस्थितियों और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बाद में बंबई उच्च न्यायालय ने उन्हें शहत प्रदान करते हुए अग्रिम जमानत दे दी, जिसके खिलाफ शिकायतकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा ढटखटया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का विस्तृत परीक्षण करने के बाद पाया कि आरोप प्रथम स्पष्ट्या गंभीर हैं और दुपने पुलिस अधिकारियों द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग का स्पष्ट आरोप शामिल है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में न्यायिक दृष्टिकोण अत्यंत सावधानीपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह केवल एक व्यक्ति के साथ अन्याय का मामला नहीं रह जाता, बल्कि पूरे पुलिस तंत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा जाता है। अदालत ने यह भी कहा कि कानून लागू करने वाली संस्थाओं की साख लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिलाओं में से एक है। यदि नागरिकों के यह महसूस होने लगे कि सुरक्षा देने वाली एजेंसियाँ ही उनके लिए खतरा बन सकती हैं, तो कानून के शासन की अवधारणा कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए ऐसे मामलों में निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित करना आवश्यक है।



इस हादसे का सबसे दुःखद पहलू यह रहा कि मृतकों में अधिकांश विदेशी नागरिक थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतकों में लाइबेरिया, नाइजीरिया, मोजाम्बिक और बांग्लादेश के नागरिक शामिल हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक होटल में उठरने वाले अधिकांश विदेशी नागरिक चिकित्सा उपचार के लिए दिल्ली आए थे। साकेत स्थित मैक्स

कि रेलवे स्टेशन पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तीनों को रोक लिया और छुट्टाछ के नाम पर हिरासत में ले लिया। इसके बाद उनको सामान की तलाशी ले ली, जिसमें 14 ग्राम की एक सोने की छड़ और 31,900 रुपये नकद मिले। शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने सोने की छड़ और नकदी के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण भी दिया था। इसके बावजूद पुलिसकर्मियों उन्हें स्टेशन परिसर के पास स्थित एक कमरे में ले गए। वहां कथित तौर पर उन्हें धमकी पाया गया, अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया और मानसिक दबाव बनाया गया। आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने सोने की छड़ के बदले नकद राशि देने के लिए उन्हें जबूर किया और अपनी शक्ति का अनुचित इस्तेमाल किया। घटना के बाद शिकायतकर्ता ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रार्थमिकी दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू हुई और आरोपित पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की मांग की। हालांकि सत्र अदालत ने मामले की परिस्थितियों और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए उनको अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बाद में बंबई उच्च न्यायालय ने उन्हें राहत प्रदान करते हुए अग्रिम जमानत दे दी, जिसके खिलाफ शिकायतकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा ढकढकया।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले का विस्तृत परीक्षण करने के बाद पाया कि आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर हैं और इनमें पुलिस अधिकारियों द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग का स्पष्ट आरोप शामिल है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में न्यायिक दृष्टिकोण अत्यंत सावधानीपूर्वक होना चाहिए, क्योंकि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह केवल एक व्यक्ति के साथ अन्याय का मामला नहीं रह जाता, बल्कि पूरे पुलिस तंत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा जाता है। अदालत ने यह भी कहा कि कानून लागू करने वाली संस्थाओं की सख्त लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिलाओं में से एक है। यदि कानूनों को यह सहस्र होंगे लोग कि सुरक्षा देने वाली एजेंसियां ही उनको लिए खतरा बन सकती हैं, तो कानून के शासन की अवधारणा कमजोर पड़ जाती है। इसलिए ऐसे मामलों में निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित करना आवश्यक है।

असत्ताल को निकटता के कारण बड़ी संख्या में विदेशी मजदूर और उनके परिवार इस होटल में रुकते थे। असत्ताल से मात्र सीढ़ी कोट की दूरी पर स्थित होने के कारण यह होटल मेडिकल टूरिज्म से जुड़े लोगों के बीच लोकप्रिय माना जाता था।

कमरे में सामने आए तथ्यों ने हादसे को और गंभीर बना दिया है। बताया जा रहा है कि होटल बिना वैध अतिथिमान अनापित प्रमाणपत्र (फायर एनसोर्ट) के संचालित किया जा रहा था। होटल की वेबसाइट पर आधुनिक सुविधाओं, आसन परिवहन व्यवस्था और असत्ताल की निकटता पर प्रचार किया गया था, लेकिन भवन को सुरक्षा प्रचारा की को लेकर गंभीर खामियाँ मौजूद थीं। आग लगने के बाद सामने आया कि प्रवेश भवन को केवल छह कमरों वाले गैरेज हाउस के रूप में अनुमति मिली थी, उसी भवन में छह मंजिला संरचना खड़ी कर 26

कमरे और एक रेस्टोरेन्ट संचालित किया जा रहा था। अधिकारियों के अनुसार आग लगने के समय भवन में 80 से 100 लोगों को मौजूदगी थी। क्षमता से कहीं अधिक लोगों को उठराने और सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने इस दुर्घटना को और भी भयावह बना दिया। प्रांथिक जांच में यह भी देखा जा रहा है कि भवन में पर्याप्त आपातकालीन निकास व्यवस्था, अतिथिमान उपकरण और सुरक्षा उपकरण मौजूद थे या नहीं। यदि इन मानकों को पालन किया गया होता तो संभवतः जन्हाति को काफी हद तक रोका जा सकता था।

हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने होटल मालिक वनकेश बजाज और उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दोनों के खिलाफ लुकाआउट संकुलन की जारी किया गया है। पुलिस की टीम उनके आवास पर पहुंची, लेकिन वे वहां नहीं मिले। एफआईआर दर्ज होने के बाद से दोनों फरार बाग जा रहे हैं।

प्रमाली के आधार पर होता है। इस बार
याद पढ़ एशिया-प्रशांत क्षेत्र के हिस्से में
आया था। शुरूआत में इस पर के लिए
तीन उम्मीदवार मैदान में थे—बांग्लादेश
साइप्रस और फिलिस्तीन। हालांकि मतदान
में पहले फिलिस्तीन के उम्मीदवार रियाद
सहने ने अपना नाम वापस ले लिया,
जिसके बाद मुकाबला बांग्लादेश और
साइप्रस बीन साह रहा था।
डॉ. खलीलु रहीमान का चयन उनकी
लंबी कूटनीतिक यात्रा और अंतरराष्ट्रीय
अनुभव का परिणाम माना जा रहा है।
हार्वर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षित रहाना
एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, राजनयिक और
नीति विशेषज्ञ हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र
संस्थान में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ
निभाई हैं। इसके अलावा रोहिंया शरणार्थी
सम्वेद के दौरान वे बांग्लादेश सरकार के
उच्च प्रतिनिधि के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर
पर सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। हाल के
वर्षों में उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और विश्व
नीति से जुड़े कई अहम दायित्व संभाले हैं।

जुलूस की विशेष टीमों में उनकी तलाश में जुटी हुई है और संभावना जाईजं जा रहा है। कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

हजार त्रासदी में एक बार फिर राजधानी में भवन सुरक्षा और अग्निरक्षण नियमों के पालन को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। दिल्ली की मेयर प्रवेश वाही ने घटना को अत्यंत चिंताजनक बताते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने निगम आयुक्त संजीव खिरवार को पत्र लिखकर तीन दिनों के भीतर विस्तृत जांच प्रोटोकॉल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जांच में भवन निर्माण नियमों, अग्नि सुरक्षा मानकों और प्रशासनिक स्तर पर हुई संभावित लापरवाही को पड़ताल की जाएगी।

मेयर ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध पाई जाएगी है तो उसे खिलफत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि इतने बड़े पैमाने पर भवन नियमों का उल्लंघन होने के बावजूद संबंधित विभागों में समान रहते कारवाई क्यों नहीं की। यह सवाल भी उठ रहा है कि विना वैंड वैध फायर एनओसी के होलर वर्षों तक कैसे पालन संभालित होता रहा। इस हादसे ने केवल 21 परिवारों को अपूरणीय क्षति नहीं पहुंचाई, बल्कि दिल्ली की शहरी सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को भी उजागर कर दिया गया है। राजधानी में बड़ी संख्या में ऐसे होलर, गैस्ट हाउस और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में संस्थानित हो रहे हैं, जहां सुरक्षा मानकों का पालन केवल कागजों तक सीमित है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसे घटना से सबक नहीं लिया गया तो भविष्य में भी ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति हो सकती है। होजरा रानी का यह अग्निकांड केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही, निर्माणों की अनदेखी और सुरक्षा मानकों की उपेक्षा का दुखद परिणाम बनकर सामने आया है।



बांग्लादेश के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि इससे पहले वर्ष १९८६ में तत्कालीन विदेश मंत्री हुमायून राशिद चौधरी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने गए थे। लगभग चालीस वर्षों के बाद एक बार फिर किसी बांग्लादेशी नेता को यह जिम्मेदारी मिली है। हाका में इस जीत को देश की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और सन्निकृष्ट कूटनीतिक भूमिका का प्रमाण माना जा रहा है। दूसरी ओर, साइप्रस के उम्मीदवार एंड्रियास एस. काकोरिस भी अंतरराष्ट्रीय शक्तिगत के अनुभवी चेहरा रहे हैं। चार दशकों से अधिक समय तक विभिन्न देशों में राजदूत और वरिष्ठ राजनयिक के रूप में कार्य कर चुके काकोरिस ने अपने चुनाव अभियान में “हमारा घर, हमारा भविष्य, हमारी जिम्मेदारी” विषय को केंद्र में रखा था। हालांकि अंततः उन्हें अपेक्षित समर्थन नहीं मिला।

भारत ने भी खलीलुर रहमान की जीत का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय डॉ. एस. जयशंकर ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि भारत बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और साझा वैश्विक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने का इच्छुक है। जयशंकर ने सोशल

मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के ८१वें सत्र के अध्यक्ष चुने जाने पर डॉ. खलीलुर रहमान को हार्दिक बधाई। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में वैश्विक सहयोग और मजबूत होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वथनेनी हरीश ने भी रहमान को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत हमेशा संयुक्त राष्ट्र के केंद्रित बहुपक्षवाद का समर्थन करता रहेगा और उन्हें अन्य कार्यवाहक के लिए सफलता की शुभकामनाएं दें।

यद्यपि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का पद प्रत्यक्ष कार्यकारी शक्तियों वाला नहीं माना जाता, फिर भी इसकी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महासभा वह मंच है जहां दुनिया के सभी सदस्य देश समान अधिकारों के साथ अपनी बात रखते हैं। यहां पारित होने वाले प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, लेकिन वे वैश्विक जनमत और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सामूहिक सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के वजेट, विकास कार्यक्रमों, मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन और अंतरराष्ट्रीय शांति से जुड़े अनेक विषयों पर महासभा की भूमिका निर्णायक मानी जाती है। हाल के वर्षों में यूक्रेन युद्ध और गाजा संघर्ष जैसे मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो के प्रयोग के कारण कई बार निर्णय प्रक्रिया बाधित हुई है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऋतब्रत बनर्जी का यह कदम रणनीतिक

JioTV
CHENNAI NO.
2063

dailyhunt

ebaba Tv

dish tv SMART+

firetv

Roku

**वीनतम समाचार
लिए आज ही
हिंदी चेनल देखिये**

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चैनल देखिये

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 5 जून को गुजरात दौरे पर : 12,421 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 5 जून, 2026 यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर सूरत-गुजरात के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे के दौरान वे दक्षिण गुजरात क्षेत्र को 12,421 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भेंट देंगे।

श्री मोदी वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे के दो पैकेजों का लोकार्पण करेंगे तथा चार अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग की इन परियोजनाओं से दक्षिण गुजरात सहित पूरे राज्य में कनेक्टिविटी बेहतर होगी तथा स्थानीय आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

एनएच-56 के अपग्रेडेशन से जनजातीय जिलों की कनेक्टिविटी होगी मजबूत



गुजरात में एनएच-56 के अपग्रेडेशन के अंतर्गत धर्मासिया-बिटाड़ा और नसारपोर-मलोथा सेक्शन को फोरलेन बनाने से स्ट्रेच्यू ऑफ यूनिटी तथा इस क्षेत्र के जनजातीय जिलों (नर्मदा, तापी, वलसाड, छोटा उदेपुर) तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ये फोरलेन सड़कें किसानों, उद्योगों और ट्रेड रूट को जोड़कर स्थानीय विकास में योगदान देंगी। 107.67 किलोमीटर की कुल लंबाई की इस फोरलेन सड़क के निर्माण से यात्रा का समय 40 मिनट तक कम हो जाएगा जबकि औसत गति में 75 फीसदी की वृद्धि देखने को मिलेगी। यह फोरलेन सड़क फार्मा, मेडिकल क्लस्टर, फिशिंग सी-फूड क्लस्टर, इस क्षेत्र के जनजातीय जिलों तथा लॉजिस्टिक्स नोड्स (एक एयरपोर्ट, 02 रेलवे स्टेशन और 02 बंदरगाह) को जोड़ेगी।

7689 करोड़ रुपए के खर्च से निर्मित वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे (पैकेज 6 और 7) का लोकार्पण

एनएच-56 के अपग्रेडेशन के अंतर्गत धर्मासिया-बिटाड़ा और नसारपोर-मलोथा सेक्शन को फोरलेन बनाने के कार्य का शिलान्यास

हजीरा में 149 करोड़ रुपए के खर्च से बनेगा 6-लेन अंडरपास और फ्लाईओवर, भारी वाहनों की आवाजाही होगी सुगम

दक्षिण गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी और मजबूत होगी, आर्थिक विकास को मिलेगी गति



7689 करोड़ रुपए के खर्च से तैयार वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे (पैकेज 6 और 7) का लोकार्पण

प्रधानमंत्री के करकमलों से वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 36 किलोमीटर लंबे कीम-एना सेक्शन (पैकेज 6) और 27.50 किलोमीटर लंबाई के गणदेवा से एना सेक्शन (पैकेज 7) का लोकार्पण होगा। इन दोनों पैकेजों का निर्माण 7689 करोड़ रुपए के खर्च से किया गया है। इन दोनों पैकेजों में मेजर ब्रिज, माइनर ब्रिज, रेल रोड ब्रिज, फ्लाईओवर्स और व्हीकल अंडरपास (वीओपी) का व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया है। स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए दोनों पैकेजों में कुल 70 अंडरपास और 2 इंटरचेंज बनाए गए हैं। 8 लेन सड़क की शुरुआत होने से इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी और मजबूत होगी और त्वरित परिवहन संभव होगा। ड्राइवरों की सुरक्षा और सक्षूलित बढ़ाने के लिए इन दोनों पैकेजों को कुल 7 सुविधा युक्त रेस्ट परिया बनाए जाएंगे। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर इन दो पैकेजों के शुरू होने से आने वाले माल ढुलाई और तेज होगी तथा भारतमाला परियोजना के लक्ष्य के अनुसार स्थानीय उद्योगों के लिए लॉजिस्टिक्स के खर्च को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) की 4732 करोड़ रुपए के खर्च से चार अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा, जिनमें एनएच-56 (पैकेज 4) के धर्मासिया से बिटाड़ा/मोवी की फोरलैनिंग, एनएच-56 (पैकेज 6) के नसरपोर से मलोथा की फोरलैनिंग, सूरत हजीरा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-53) पर सिक्स लेन वीथूपी यानी व्हीकल अंडरपास (रिलायंस) और वीथूपी कम फ्लाईओवर (कावास) शामिल हैं।



हजीरा में बनेगा सिक्स लेन का फ्लाईओवर और व्हीकल अंडरपास

राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के हजीरा बंदरगाह-सूरत विभाग पर लगभग 149 करोड़ रुपए की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। नए 6-लेन फ्लाईओवर और अंडरपास के निर्माण से हजीरा पोर्ट और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भारी मालवाहक वाहनों की अवरोध मुक्त एवं त्वरित आवाजाही सुनिश्चित होगी। इससे समुद्री व्यापार और औद्योगिक विकास के साथ-साथ सूरत के स्थानीय लोगों को सुरक्षित और यातायात जाम से मुक्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस फ्लाईओवर और अंडरपास के निर्माण से हजीरा बंदरगाह के निकट स्थित भारी औद्योगिक क्षेत्र में भीड़ कम होगी और सुगम परिवहन सुनिश्चित होगा।

अहमदाबाद में अवैध घुसपैठियों पर सबसे बड़ी कार्रवाई, 131 बांग्लादेशी गिरफ्तार



अहमदाबाद। गुजरात में अवैध रूप से रह रहे विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक की सबसे बड़ी संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। अहमदाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में 131 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 160 अन्य संदिग्धों से गहन पूछताछ की जा रही है। राज्य सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान आगे भी और अधिक सख्ती के साथ जारी रहेगा।

मिली जानकारी के अनुसार अहमदाबाद के चांदोला, गुलाबनगर और खोडियारनगर क्षेत्रों में देर रात व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस, क्राइम ब्रांच और अन्य जांच एजेंसियों की कई टीमों ने एक साथ अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान करीब 290 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक दस्तावेजी जांच और पहचान सत्यापन की प्रक्रिया के बाद 131 लोगों की पहचान अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के रूप में हुई, जिन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया।

अधिकारियों के अनुसार जांच में सामने आया है कि कई घुसपैठिए लंबे समय से फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और अन्य पहचान दस्तावेजों के सहारे शहर में रह रहे थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन लोगों को नकली दस्तावेज उपलब्ध कराने और स्थानीय स्तर पर बसाने के पीछे कौन लोग और नेटवर्क सक्रिय है। आशंका जताई जा रही है कि इस पूरे रैकेट में दलालों और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोहों

की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हिरासत में लिए गए 160 अन्य लोगों के दस्तावेजों और नागरिकता संबंधी रिकॉर्ड की भी बारीकी से जांच की जा रही है। उनके स्थानीय संपर्कों, रोजगार के स्रोतों और निवास संबंधी जानकारीयों को खंगाला जा रहा है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि क्या इन लोगों का संबंध किसी संगठित नेटवर्क या अवैध गतिविधियों से रहा है।

इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी जब्त किए हैं। जांच टीमों का मानना ​​है कि इन दस्तावेजों से फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले गिरोहों और अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले तत्वों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। अधिकारियों के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

गुजरात के उपमुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने इस अभियान को राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि गृह विभाग ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद के अलावा सूरत, राजकोट और वडोदरा जैसे प्रमुख शहरों में भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कर उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

हर्ष संघवी ने कहा कि पुलिस, क्राइम ब्रांच, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) और अन्य सुरक्षा एजेंसियां समन्वित तरीके से काम कर रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों

में लगातार तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता कानून-व्यवस्था बनाए रखना और अवैध घुसपैठ पर पूरी तरह रोक लगाना है।

सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और नागरिकता संबंधी औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके देश वापस भेजने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके साथ ही फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले लोगों और उन्हें शरण देने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

सुरक्षा एजेंसियों का मानना ​​है कि यह अभियान केवल अवैध घुसपैठियों की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए उन संगठित नेटवर्कों को भी ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है जो वर्षों से फर्जी दस्तावेजों और अवैध प्रवास को बढ़ावा दे रहे हैं। राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे अभियान और तेज किए जाएंगे तथा किसी भी अवैध विदेशी नागरिक को बख्शा नहीं जाएगा।

अहमदाबाद में हुई यह कार्रवाई हाल के वर्षों में अवैध घुसपैठ के खिलाफ चलाए गए सबसे बड़े अभियानों में से एक मानी जा रही है। इससे सुरक्षा एजेंसियों को न केवल अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करने में सफलता मिली है, बल्कि उन नेटवर्कों तक पहुंचने का भी अवसर मिला है जो इस पूरे तंत्र को संचालित कर रहे थे। अब जांच एजेंसियों की नजर इस बात पर है कि इस मामले के तार राज्य के अन्य शहरों और बाहरी राज्यों तक तो नहीं जुड़े हुए हैं।

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। भीषण गर्मी से जुझ रहे कई राज्यों को अब बारिश, तेज आंधी और ठंडी हवाओं से राहत मिलने लगी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर, दक्षिण, पूर्वोत्तर और मध्य भारत के अनेक हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम सक्रिय बना रहेगा। कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश होगी तो कहीं ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम में आए इस बदलाव के काफ़ी करीब 18 राज्यों में सामान्य जनजीवन प्रभावित होने के साथ-साथ लोगों को गर्मी से बड़ी राहत भी मिली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने 4 और 5 जून के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बुधवार को राजधानी का अधिकतम तापमान करीब 38 डिग्री सेल्सियस और

है। कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी व्यवक्त की गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी गतिविधियों के कारण दिल्ली-एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक मौसम सुहावना बना रह सकता है। इस बीच दक्षिण-पश्चिम मानसून भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु तथा बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं। मानसून की प्रगति के साथ देश के कई क्षेत्रों में वर्षा गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में अगले पांच दिनों तक मौसम काफी सक्रिय रहने वाला है। अरुणाचल प्रदेश में 3 से 8 जून के बीच भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं असम और मेघालय के कई क्षेत्रों में 5 से 8 जून के बीच तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और निचले इलाकों में जलप्रपाव

की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। दक्षिण भारत में मानसून की सक्रियता स्पष्ट दिखाई देने लगी है। केरल और लक्षद्वीप में लगातार बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरल में 3 से 8 जून तक बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। तेलंगाना में भी अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश और आंधी का अनुमान जताया गया है। कुछ क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा बन हुआ है।

राजस्थान में मौसम के बदले मिजाज ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है। राज्य के कई जिलों में पिछले दिनों हुई बारिश के कारण तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। चित्तौड़गढ़ में सबसे अधिक 61 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। हालांकि फलौदी अभी भी 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ राज्य का सबसे गर्म शहर बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी भी चल सकती है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम ने राहत पहुंचाई है। राजधानी लखनऊ का अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि फतेहगढ़ 42 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने किसानों और खुले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।

पूवी भारत के राज्यों में भी मौसम सक्रिय बना हुआ है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। ओडिशा में तेज हवाएं चल सकती हैं जबकि उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में भारी वर्षा का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी वर्षा गतिविधियां तेज बनी रहेंगी।

उत्तर-पश्चिम भारत में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के साथ कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना व्यवक्त की गई है। जम्मू-कश्मीर में ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों को मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही सफर करने की सलाह दी गई है।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, विदर्भ, महाराष्ट्र और कोंकण-गोवा क्षेत्र में भी मौसम सक्रिय रहेगा। इन राज्यों के कई सावधानी बरतने की सलाह दी है।

मानसून से पहले गुजरात अलर्ट: ‘जीरो कैजुअल्टी’ के लक्ष्य के साथ प्रशासन सज्ज : मुख्य सचिव श्री एम. के. दास

- ▶ मुख्य सचिव श्री एम. के. दास की अध्यक्षता में गांधीनगर में प्री-मानसून उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई
- ▶ संबंधित विभागों और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने मानसून पूर्व तैयारियों तथा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान पर प्रस्तुतियां दीं
- ▶ राज्य में बचाव कामकाज के लिए एनडीआरएफ की 14 और एसडीआरएफ की 22 टीमों तैयार



गांधीनगर : मुख्य सचिव श्री एम. के. दास की अध्यक्षता में बुधवार को गांधीनगर में आगामी मानसून की संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों तथा विभागों की प्री-मानसून उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस महानिदेशक, मुख्य वन संरक्षक का भी अवसर मिला है जो इस पूरे तंत्र को संचालित कर रहे थे। अब जांच एजेंसियों की नजर इस बात पर है कि इस मामले के तार राज्य के अन्य शहरों और बाहरी राज्यों तक तो नहीं जुड़े हुए हैं।

मुख्य सचिव श्री एम. के. दास ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के निर्देशानुसार मानसून के दौरान राज्य में किसी भी प्रकार की जनहानि न हो, इसके लिए प्रशासन को पूरी तरह सतर्क और तैयार रहना चाहिए। उन्होंने नागरिकों को असुविधा से बचाने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शेष सड़कों तथा सीवर-लाइन के कार्यों का शीघ्र पूरा करने पर विशेष जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने भारी वाहनों की अधिक आवाजाही वाले मार्गों और पुलों की आवश्यक मरम्मत का कार्य अभी से पूरा करने के लिए सड़क एवं भवन

विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने आगे कहा कि पहली बारिश और तूफान के दौरान पेड़ गिरने की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय कर अभी से पेड़ों की छंटाई करें, ताकि ट्रैफिक जाम और जनहानि से बचा जा सके। मुख्य सचिव ने सरदार सरोवर और उकाई सड़कों तथा सीवर-लाइन के कार्यों का शीघ्र पूरा करने पर विशेष जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने भारी वाहनों की अधिक आवाजाही वाले मार्गों और पुलों की आवश्यक मरम्मत का कार्य अभी से पूरा करने के लिए सड़क एवं भवन

विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने आगे कहा कि पहली बारिश और तूफान के दौरान पेड़ गिरने की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय कर अभी से पेड़ों की छंटाई करें, ताकि ट्रैफिक जाम और जनहानि से बचा जा सके। मुख्य सचिव ने सरदार सरोवर और उकाई सड़कों तथा सीवर-लाइन के कार्यों का शीघ्र पूरा करने पर विशेष जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने भारी वाहनों की अधिक आवाजाही वाले मार्गों और पुलों की आवश्यक मरम्मत का कार्य अभी से पूरा करने के लिए सड़क एवं भवन

विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने आगे कहा कि पहली बारिश और तूफान के दौरान पेड़ गिरने की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय कर अभी से पेड़ों की छंटाई करें, ताकि ट्रैफिक जाम और जनहानि से बचा जा सके। मुख्य सचिव ने सरदार सरोवर और उकाई सड़कों तथा सीवर-लाइन के कार्यों का शीघ्र पूरा करने पर विशेष जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने भारी वाहनों की अधिक आवाजाही वाले मार्गों और पुलों की आवश्यक मरम्मत का कार्य अभी से पूरा करने के लिए सड़क एवं भवन

रेलवे सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में विद्यार्थियों को सुरक्षित व्यवहार अपनाने का संदेश

आरपीएफ असारवा द्वारा आईटीआई कुबेरनगर में आयोजित किया गया विशेष जन-जागरूकता कार्यक्रम



रेलवे में पथरबाजी, अनधिकृत रेल अतिक्रमण, चैन पुलिंग, रन-ओवर जैसी दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट असारवा द्वारा आईटीआई कुबेरनगर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्री अश्विमान राम निगौडी, आईआरपीएफएस, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ, अहमदाबाद मंडल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को रेलवे में होने वाली पथरबाजी, रेलवे पटरियों पर अनधिकृत रूप से चलने अथवा उन्हें पार करने से उत्पन्न होने वाले गंभीर खतरों तथा इनके कानूनी परिणामों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पथरबाजी एवं रेलवे क्षेत्र में अपने परिवारजनों, मित्रों एवं पड़ोसियों

को क्षति पहुंचाते हैं, बल्कि यात्रियों एवं रेलवे कर्मचारियों के जीवन को भी गंभीर जोखिम में डालते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से रेलवे पटरियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने, चलती ट्रेनों पर पथर न फेंकने तथा सदैव सुरक्षित व्यवहार अपनाने का आह्वान किया। साथ ही विद्यार्थियों को प्रेरित किया गया कि वे इस कार्यक्रम से प्राप्त जानकारी को अपने परिवारजनों, मित्रों एवं पड़ोसियों

तक पहुंचाकर रेलवे सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। श्री त्रिपाठी ने विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर अवसरों के संबंध में भी मार्गदर्शन प्रदान किया तथा उन्हें नशे एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों से दूर रहने की प्रेरणा दी। यह कार्यक्रम प्रभारी निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल थाना असारवा श्री मनु छोक्कर एवं उनकी टीम के विशेष प्रयासों

से आयोजित किया गया। आरपीएफ असारवा द्वारा निरंतर चलाए जा रहे जन-जागरूकता अभियानों जैसे “संवाद” एवं सामुदायिक सहभागिता के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। गत वर्ष जहां पथरबाजी की 9 घटनाएं दर्ज हुई थीं, वहीं वर्ष 2026 में मई माह तक केवल 2 घटनाएं ही दर्ज हुई हैं। यह उल्लेखनीय उपलब्धि आरपीएफ के सतत प्रयासों का प्रतिफल है। इसके बावजूद आरपीएफ असारवा इसी घटनाओं को पूर्णतः समाप्त करने के लक्ष्य के साथ निरंतर कार्यरत है। कार्यक्रम में श्री नीरव विष्णुभाई देसाई, प्राचार्य, आईटीआई कुबेरनगर सहित संस्थान के अन्य शिक्षकों की भी गरिमापूर्ण उपस्थिति रही। लगभग 200 विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता की। रेलवे सुरक्षा का सशक्त संदेश देते हुए कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।



प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आगामी 5 जून को दक्षिण गुजरात को देंगे 1063 करोड़ रुपए से अधिक के जीआईडीसी प्रोजेक्ट्स की भेंट

प्रधानमंत्री जीआईडीसी अंतर्गत भरूच में 894 करोड़ रुपए से अधिक के तथा वलसाड में 169.3 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे

▶▶**दहेज पीसीपीआईआर में प्रदूषित जल के प्रभावी निस्तारण के लिए 474.61 करोड़ रुपए के एफ्लुएंट पाइपलाइन प्रोजेक्ट का लोकार्पण होगा**

▶▶**जंबूसर बल्क ड्रग पार्क में 274.96 करोड़ रुपए की लागत से रोड, स्टॉर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क तथा सेंट्रल ड्रेन की सुविधाओं से फार्मा क्लस्टर के विकास को मिलेगी नई गति**

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आगामी 5 जून, 2026 को गुजरात की यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान वे सूरत से भारत सरकार एवं गुजरात सरकार के कुल मिलाकर 18,777 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास करेंगे। दक्षिण गुजरात अंचल के विकास को वेग देने वाले इन विकास कार्यों में गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) अंतर्गत 1063.43 करोड़ रुपए की लागत से 8 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण शामिल है। इसके तहत भरूच को 894 करोड़ रुपए से अधिक के तथा वलसाड को 169.3 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भेंट मिलने जा रही है। इन प्रोजेक्ट्स से दक्षिण गुजरात के औद्योगिक क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रदूषित जल निस्तारण तथा ड्रेनज व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

प्रधानमंत्री भरूच में 894 करोड़ रुपए से अधिक के 6 जीआईडीसी प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे

भारत के औद्योगिक विकास में गुजरात हमेशा शीर्ष पर रहा है, जिसमें भरूच जिला केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल उद्योग के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरकर आया है। भरूच की औद्योगिक क्षमता को अधिक



Sarigam CETP

सशक्त बनाने के प्रयासों के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री 894 करोड़ रुपए से अधिक के 6 जीआईडीसी प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे। दहेज पीसीपीआईआर औद्योगिक क्लस्टर में सायखा पंपिंग स्टेशन से दहेज के लैंडफॉल पॉइंट तक 90 एमएलएडी क्षमता की ऑफशोर व ऑनशोर एफ्लुएंट निस्तारण पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। इसमें 5 वर्ष के ऑपरेशन तथा मंटेनेंस

(ओ एंड एम) के साथ सिविल स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कम्पोनेंट्स और पीएलसी स्काडा सिस्टम्स का डिजाइन, इरेक्शन, टेस्टिंग तथा कमीशनिंग शामिल हैं। 474.61 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से दहेज तथा सायखा औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषित पानी के निस्तारण एवं प्रबंधन को और मजबूती मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि दहेज पीसीपीआईआर क्षेत्र में मुख्यतः रासायनिक, टेक्सटाइल, फार्मा, डाइज एवं इंटरमीडिएट, इंजीनियरिंग उद्योगों के विकास के लिए ढाँचागत सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं। हाल में इस क्षेत्र में 1,000 से अधिक औद्योगिक इकाइयों कार्यरत हैं। इसके अलावा; भरूच जिले के जंबूसर स्थित बल्क ड्रग पार्क में फार्मास्यूटिकल उद्योगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर रोड, स्टॉर्म वाटर ड्रेनज नेटवर्क तथा सेंट्रल ड्रेन जैसी महत्वपूर्ण अंतर्र्ढाँचागत सुविधाएँ विकसित की गई हैं। 274.96 करोड़ रुपए के खर्च से शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट से बल्क ड्रग पार्क के ढाँचागत विकास को वेग मिलेगा।

प्रधानमंत्री दहेज-2 औद्योगिक बस्ती (क्षेत्र/परिसंपदा) के लिए 30 एमएलडी ड्रेनज पंपिंग स्टेशन का भी लोकार्पण करेंगे। उल्लेखनीय है कि दहेज-2 औद्योगिक बस्ती में सुवा पंपिंग स्टेशन से अंतिम पंपिंग स्टेशन जेड-93 तक राइजिंग मेन के साथ 30 एमएलडी क्षमता के ड्रेनज पंपिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट से औद्योगिक ड्रेनज प्रबंधन अधिक कार्यक्षम बनेगा तथा एकीकृत एफ्लुएंट वहन नेटवर्क को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा; पानोली विस्तार औद्योगिक क्षेत्र में पर्लेक्सबल रोड पेवमेंट, क्रॉस ड्रेनज वर्क, जलापूर्ति नेटवर्क, कम्पाउंड वॉल, पेवर ब्लॉक, वृक्षारोपण और स्ट्रीट लाइट सहित विभिन्न ढाँचागत सुविधाओं का विकास किया गया है। इन विकास कार्यों से इस औद्योगिक क्षेत्र में अधिक अच्छी ढाँचागत सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। अन्य प्रोजेक्ट्स में अंकलेश्वर में एफ्लुएंट ट्रांसमिशन पाइपलाइन पर इंटरमीडिएट बूस्टर पंपिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट से प्रदूषित जल का कार्यक्षम वहन तो होगा ही, साथ ही पर्यावरणीय मानदंडों का संरक्षण भी सुनिश्चित होगा। इसी प्रकार; दहेज-1 औद्योगिक बस्ती की वर्षा जल वहन क्षमता सुधारने, जल भराव के जोखिम कम करने तथा क्षेत्र के समग्र वर्षा जल की निकासी को व्यवस्था के ढाँचे

को मजबूत करने के लिए नेचुरल ड्रेन-2 का अपग्रेडेशन किया गया है।

वलसाड में 169 करोड़ रुपए से अधिक के जीआईडीसी प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण

वलसाड जिले के सरीगाम में प्रधानमंत्री जीआईडीसी के दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे। इसके तहत सरीगाम स्थित कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) की क्षमता 15 एमएलडी से बढ़ाकर 25 एमएलडी की गई है। इससे प्रदूषित जल के शुद्धिकरण की क्षमता में वृद्धि होगी और पर्यावरणीय मानदंडों का प्रभावी पालन सुनिश्चित होगा। इस प्रोजेक्ट में डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कन्स्ट्रक्शन, कमीशनिंग, टेस्टिंग, ट्रायल रन तथा ऑपरेशन मंटेनेंस और रिपेयरिंग कार्य शामिल हैं। इसके अलावा; सरीगाम औद्योगिक बस्ती (क्षेत्र) में संप तथा पंपिंग स्टेशन के साथ एचडीपीई ऑनशोर व ऑफशोर आउटफॉल पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट अंतर्गत पंपिंग स्टेशन से लैंडफॉल चैम्बर तथा गहरे समुद्र में निस्तारण के स्थल तक एचडीपीई ऑनशोर व ऑफशोर पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया गया है।

गर्मियों में माथे का कालापन कैसे करें दूर? अपनाएं आसान घरेलू उपाय और लौटाएं त्वचा की प्राकृतिक चमक- शहनाज हुसैन

गर्मियों का मौसम जहां धूप, गर्म हवाओं और पसीने के कारण त्वचा को कई तरह की चुनौतियां देता है, वहीं माथे पर कालापन या पिग्मेंटेशन की समस्या भी इन दिनों काफी आम हो जाती है। कई लोग यह महसूस करते हैं कि चेहरे का बाकी हिस्सा अपेक्षाकृत साफ दिखाई देता है, लेकिन माथे की त्वचा अधिक सांवली, बेजान और काली नजर आने लगती है। यह समस्या केवल सौंदर्य को प्रभावित नहीं करती, बल्कि कई बार आत्मविश्वास पर भी असर डालती है।

माथे का कालापन कई कारणों से हो सकता है। सबसे प्रमुख कारण सूरज की तेज परावर्गीय किरणें हैं, जो त्वचा में मेलैनिन के उत्पादन को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा अत्यधिक पसीना आना, त्वचा की सही देखभाल न करना, पोषण की कमी, हार्मोनल परिवर्तन, धूल-मिट्टी का प्रभाव तथा त्वचा की संवेदनशीलता भी इसके पीछे जिम्मेदार हो सकती हैं। कई बार लोग बार-बार माथे को रगड़ते रहते हैं, जिससे त्वचा पर घर्षण बढ़ जाता है और धीरे-धीरे वहां पिग्मेंटेशन विकसित होने लगता है।

सिरदर्द होने पर बार-बार बाम लगाने की आदत भी कुछ लोगों में माथे के कालेपन का कारण बन सकती है। बाम में मौजूद कुछ रासायनिक तत्व संवेदनशील त्वचा पर प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार बालों में हेयर कलर का बार-बार उपयोग करने से भी माथे की त्वचा प्रभावित हो सकती है। हेयर डाई में मौजूद केमिकल्स कई बार एलर्जी या त्वचा के रंग में बदलाव का कारण बन जाते हैं। कुछ लोगों को परफ्यूम या सुगंधित उत्पादों से भी एलर्जी होती है, जिसके परिणामस्वरूप माथे की त्वचा पर कालापन या दाग-धब्बे



उभर सकते हैं।

अक्सर यह समस्या इतनी स्पष्ट हो जाती है कि माथे और चेहरे की त्वचा के रंग में अंतर साफ दिखाई देने लगता है। विशेष रूप से श्रेडिंग या फेशियल करवाने के बाद यह अंतर अधिक स्पष्ट नजर आता है। ऐसे में कई लोग महंगे कॉस्मेटिक उपचारों का सहारा लेते हैं, जबकि कुछ सरल घरेलू उपायों से भी इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

ओट्स और छाछ का मिश्रण माथे के कालेपन को कम करने का एक प्रभावी घरेलू उपाय माना जाता है। ओट्स त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है, जबकि छाछ में मौजूद प्राकृतिक तत्व त्वचा को कोमल बनाकर उसकी रंगत निखारने में सहायक होते हैं। इसके लिए दो चम्मच ओट्स को थोड़े पानी में भिगो दें। लगभग पांच मिनिट बाद इसमें तीन चम्मच छाछ मिलाएं और इस मिश्रण से माथे तथा चेहरे पर हल्के हाथों से मालिश करें। लगभग आधे घंटे बाद साफ पानी से चेहरा धो लें। इसके बाद हल्का मॉइश्चराइजर लगाया जा सकता है। सप्ताह में दो से तीन बार इस उपाय को अपनाने से त्वचा में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगते हैं।

है। सोने से पहले कच्चे दूध में गुलाब जल मिलाकर माथे पर लगाएं और रातभर लगा रहने दें। सुबह उठकर चेहरे को साफ पानी से धो लें। नियमित उपयोग से त्वचा की रंगत में सुधार देखने को मिल सकता है।

शहद और नींबू का मिश्रण भी माथे के कालेपन को कम करने के लिए लोकप्रिय घरेलू नुस्खा है। शहद त्वचा को नमी प्रदान करता है जबकि नींबू में प्राकृतिक ब्लीचिंग गुण पाए जाते हैं। एक चम्मच शहद में आधा चम्मच नींबू का रस मिलाकर माथे पर लगाएं और लगभग 30 से 45 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद पानी से धो लें। यह मिश्रण त्वचा पर जमी गंदगी और अतिरिक्त मेलैनिन को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि यदि आपको त्वचा बहुत संवेदनशील है तो नींबू का उपयोग सावधानी से करें और पहले पैच टेस्ट अवश्य कर लें।

प्राकृतिक तेल भी त्वचा की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नारियल तेल, बादाम तेल और ऑलिव ऑयल में मौजूद फैटी एसिड त्वचा को पोषण प्रदान करते हैं और उसकी मरम्मत में सहायता करते हैं। इनमें से किसी भी तेल से माथे की हल्की मालिश करने के बाद कुछ समय के लिए छोड़ दें और फिर चेहरा धो लें। सप्ताह में तीन से चार बार इस उपाय को अपनाने से त्वचा नरम और स्वस्थ बनी रहती है।

एक अन्य उपयोगी घरेलू उपाय के लिए अचमूच बादाम तेल में थोड़ा शहद और दूध पाउडर मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को माथे पर लगाकर सुखने दें। सुखने के बाद हल्के हाथों से रगड़ते हुए साफ करें और पानी से धो लें। शहद त्वचा की गहराई से सफाई करता है तथा उसके प्राकृतिक रंग को उभारने में मदद कर सकता है।

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के चिकित्सा विभाग द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMS), श्रीमती भानुमति शेखर के मार्गदर्शन में मई 2026 के दौरान कर्मचारियों, उनके आश्रितों तथा आमजन के स्वास्थ्य एवं कल्याण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों, आपदा प्रबंधन अभ्यासों और जन-जागरूकता कार्यक्रमों का व्यापक स्तर पर आयोजन किया गया। इन पहलों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, आपदा प्रबंधन क्षमता बढ़ाने तथा निवारक स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए।

1. स्वीट्चक रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य जागरूकता दिवस:

▶▶अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस: इस अवसर पर मंडलीय रेलवे अस्पताल, साबरमती (DRH-SBI) में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के सहयोग से एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने भाग लिया और कुल 43 यूनिट रक्त एकत्र किया गया।

▶▶विश्व अस्थमा दिवस : पूरे मंडल में जागरूकता पोर्टल्स प्रदर्शित किए गए, DRH-SBI में पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. जैमिन द्वारा व्याख्यान दिया गया और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट (PFT) स्क्रीनिंग कैप आयोजित किया गया। इस अभियान से मंडल के 200 लाभार्थी लाभान्वित हुए।

▶▶राष्ट्रीय डंगू दिवस एवं विश्व तंबाकू निषेध दिवस : इन अवसरों पर सभी रेलवे अस्पतालों, स्वास्थ्य इकाइयों (Health Units) और कॉलोनियों में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, जागरूकता शैलियां और पोस्टर प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया।



आयोजन किया गया।

▶▶29 मई को डीजल शोड, वटवा में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सत्र: इन कार्यक्रमों में रेलवे स्टाफ और उनके परिवारों ने भारी संख्या में भाग लिया।

4. प्रिवेंटिव हेल्थकेयर और सैनिटेशन ड्राइव:

▶▶मानसून से पहले मलेरिया और मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए टीकाकरण शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 40 लाभार्थियों को टीका लगाया गया।

3. मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन सत्र: कर्मचारियों के मानसिक कल्याण और कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए डॉ. मनोजकुमार देव, ACMS साबरमती द्वारा विशेष इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए गए:

▶▶26 मई को विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस पर DRH-SBI में हेल्थ वर्क।

▶▶28 मई को इंजीनियरिंग कर्मशोप, साबरमती में तनाव प्रबंधन कार्यक्रम।

देश में पहली बार : गुजरात में ‘सेवा आयुक्तालय’ की स्थापना करने का राज्य सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय

अब गुजरात के शहर बनेंगे अधिक स्मार्ट और सुरक्षित

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कैबिनेट बैठक में ‘गुजरात वायर फ्री सिटी मिशन’ को मंजूरी दी : प्रवक्ता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी

▶▶गुजरात में उद्योगों के लिए जैसे ‘उद्योग आयुक्तालय’ कार्यरत है, उसी प्रकार अब सेवा क्षेत्र के लिए अलग ‘सेवा आयुक्तालय’ कार्यरत होगा : ▶▶मैन्यूफैक्चरिंग के बाद अब सर्विस सेक्टर में भी गुजरात बनेगा देश का हब ▶▶आयुक्तालय में वर्ष 2026-27 के लिए 100 करोड़ रुपए के ‘सर्विस सेक्टर ग्रोथ फंड’ की व्यवस्था ▶▶सेवा क्षेत्र के आईटी, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों के एमएसएमईस और स्टार्टअप्स को मिलेगा वेग

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस निर्णय की घोषणा करते हुए प्रवक्ता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने देश में पहली बार गुजरात में सर्विस सेक्टर अर्थात सेवा क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता देते हुए एक अलग ‘सेवा आयुक्तालय’ की स्थापना करने तथा ‘सेवा आयुक्त’ का आधिकारिक पद सृजित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि जैसे उद्योगों के विकास के लिए विशिष्ट उद्योग आयुक्तालय कार्यरत है, उसी प्रकार अब सेवा क्षेत्र के लिए यह नई व्यवस्था शुरू कर गुजरात एक बार फिर देश के अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बनने जा रहा है। गुजरात पारंपरिक रूप से अपनी मैन्यूफैक्चरिंग और औद्योगिक क्षमता के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से अधिक संतुलित और गतिशील अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए राज्य सरकार सेवा क्षेत्र में भी विविधीकरण ला रही है। प्रवक्ता मंत्री ने आगे कहा कि ‘जीआईआईडी’ द्वारा गुजरात में सेवा क्षेत्र के सुदृढ़ और सर्वांगीण विकास के लिए सेवा आयुक्तालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था। इसके अंतर्गत वर्तमान में सेवा आयुक्तालय की स्थापना

और सेवा आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्होंने जोड़ा कि यह आयुक्तालय राज्य और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप विभिन्न सेवा उद्योगों को मजबूत आधार प्रदान करेगा। श्री वाघाणी ने कहा कि परंपरागत उत्पादन आधारित उद्योगों से आगे बढ़कर गुजरात ने सेवा क्षेत्र आधारित उद्योगों के विकास को तरफ ध्यान केन्द्रित किया है। इसके परिणामस्वरूप आईटी, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स जैसे तेजी से विकसित हो रहे सेवा क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर उत्पन्न होंगे। यह आयुक्तालय मुख्य रूप से राज्य के पर्यटन, आईटी और लॉजिस्टिक्स जैसे तेजी से विकसित हो रहे विभिन्न सेवा क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने, नई नीतियां बनाने तथा सेवा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने का केंद्र बिंदु बनेगा। उन्होंने विधायक व्यवह किया कि मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में प्राप्त वैश्विक सफलता के बाद गुजरात अब सर्विस सेक्टर के लिए भी देश का प्रमुख केंद्र बनेगा। प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल के अंतर्गत सेवा आयुक्तालय के तहत वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित 100 करोड़ रुपए के ‘सर्विस सेक्टर ग्रोथ फंड’ की स्थापना की गई है। इस ग्रोथ फंड का मुख्य उद्देश्य सेवा क्षेत्र में कार्यरत एमएसएमईस और स्टार्टअप्स को ग्रोथ कैपिटल आसानी से और समय पर उपलब्ध कराना है।

▶▶इस मिशन अंतर्गत राज्य की 17 महानगर पालिकाएं और 151 नगर पालिकाएं वायर फ्री बनेंगी ▶▶वर्ष 2030 तक राज्य के शहरी क्षेत्रों में बिजली की लाइनें पूरी तरह अंडरग्राउंड की जाएंगी ▶▶प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जनजीवन अधिक सुरक्षित बनेगा और नागरिकों को बिना किसी व्यवधान के गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलेगी

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘ग्रोन और स्मार्ट सिटी’ के विजन को साकार करते हुए ‘गुजरात वायर फ्री सिटी मिशन’ को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। इस निर्णय के संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रवक्ता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि ‘गुजरात वायर फ्री सिटी मिशन’ अंतर्गत वर्ष 2030 तक राज्य के सभी शहरों को चरणबद्ध तरीके से ‘वायर फ्री’ बनाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी मिशन के प्राथमिक चरण के लिए राज्य सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि इस मिशन

के तहत राज्य की सभी 17 महानगर पालिकाओं तथा 151 नगर पालिका क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, जिससे राज्य के शहरी क्षेत्रों की सुंदरता और सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि मिशन के अंतर्गत शहरों में वर्तमान में मौजूद ओवरहेड विद्युत विवरण नेटवर्क को पूरी तरह अंडरग्राउंड अर्थात भूमिगत केबल नेटवर्क में परिवर्तित किया जाएगा। इसके अंतर्गत 14,600 सर्किट किलोमीटर से अधिक हाई टेंशन ओवरहेड नेटवर्क तथा 31,400 सर्किट किलोमीटर से अधिक लो टेंशन ओवरहेड नेटवर्क को चरणबद्ध तरीके से भूमिगत किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में 11 केवी ओवरहेड लाइनों को तथा उसके बाद

लो टेंशन लाइनों को भूमिगत केबल नेटवर्क में परिवर्तित किया जाएगा। मंत्री ने आगे कहा कि अंडरग्राउंड केबलिंग होने से स्फुरान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तार टूटने या शॉर्ट सर्किट होने की घटनाओं को रोका जा सकेगा। इसके अतिरिक्त; तकनीकी खराबियों में कमी आने से नागरिकों को अधिक गुणवत्तापूर्ण तथा बिना किसी प्रकार की बाधा के निरंतर बिजली उपलब्ध होगी। प्रवक्ता मंत्री ने जोड़ा कि ‘गुजरात वायर फ्री सिटी मिशन’ यह केवल बिजली की लाइनों को बदलने की सामान्य प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि 21वीं सदी के स्मार्ट, सुंदर और सुरक्षित गुजरात के निर्माण की दिशा में हमारी सरकार का एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है।

12 वर्ष: विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के गुजरात के सभी जिलों में ‘विकसित भारत संकल्प सम्मेलन’ का आयोजन किया जाएगा

▶▶08 से 14 जून, 2026 के दौरान जिला मुख्यालयों में सम्मेलनों का आयोजन ▶▶‘बारह वर्ष विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के’ विषय पर वक्तव्य देंगे महानुभाव ▶▶पद्मश्री पुरस्कार विजेता, विशेषज्ञ और विभिन्न क्षेत्रों के महानुभाव रहेंगे मौजूद

गांधीनगर : गुजरात के सभी जिला मुख्यालयों में 08 से 14 जून के दौरान ‘विकसित भारत संकल्प सम्मेलन’ का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने, राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने और अंतिम छोर के व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा जनभागीदारी को बढ़ाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री, सांसद और प्रदेश स्तर से नियुक्त खास

वक्ता उपस्थित रहेंगे, जो ‘12 वर्ष विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के’ विषय पर वक्तव्य देंगे। प्रत्येक सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, प्रतिष्ठित नागरिक तथा पद्मश्री पुरस्कार विजेता भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभिन्न एसोसिएशनों, विश्वविद्यालयों, खेल संस्थानों और सामाजिक संस्थाओं का लिए आयोजित किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखा गया है कि कार्यक्रम में समाज का प्रत्येक वर्ग हिस्सा ले। इस संदर्भ

में श्रेष्ठ शिक्षक अवॉर्ड विजेता, श्रेष्ठ किसान तथा खेल क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों सहित साहित्य, कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान देने वाले महानुभाव भी हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे बड़े जिलों में दो, जबकि अन्य छोटे जिलों में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था, परिवहन व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 39,290 करोड़ रुपये की छह बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले को देश के विमानन, सड़क परिवहन और शहरी विकास क्षेत्र के लिए बड़ी राहत और प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का मानना ​​है कि इन परियोजनाओं से न केवल आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा, बल्कि रोजगार सृजन, क्षेत्रीय संपर्क और औद्योगिक विकास को भी नई

ऊर्जा प्राप्त होगी। कैबिनेट के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में विमानन क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपये के एयर टर्म्बल फ़ूल (एटीएफ) मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना शामिल है। लंबे समय से विमानन कंपनियों वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और विमानन ईंधन की कीमतों में होने की वजह से निरंतर रूप से प्रभावित होती रही है। ईंधन की कीमतों में तेजी से बढ़ते हुए एयरलाइंस के कुल परिचालन व्यय का बड़ा हिस्सा हो रहा है, जिसके कारण तेल कीमतों में वृद्धि का सीधा असर हवाई किराये और परियोजनाओं से न केवल आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा, बल्कि रोजगार सृजन, क्षेत्रीय संपर्क और औद्योगिक विकास को भी नई

बचाएगा और विमानन क्षेत्र को अधिक स्थिर एवं प्रतियस्धी बनाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार एटीएफ कोष का लाभ यात्रियों तक भी पहुंचेगा। इससे हवाई किराये में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। साथ ही एयरलाइंस के लिए वित्तीय बोझ कम होगा आसानी होगी, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के विस्तार को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है जब भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में शामिल है और आने वाले वर्षों में हवाई यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है।